भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 235
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

235. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के उद्देश्यों और प्रगति का ब्यौरा क्या है;

ख. क्या सरकार ने ई-गवर्नेंस उपकरणों को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए पंचायत अधिकारियों की डिजिटल क्षमता को सुदृढ़ बनाने और फीडबैक एकत्र करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

ग. क्या सरकार ने ई-गवर्नेंस पहलों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) का उद्देश्य पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में ई-गवर्नेंस को मज़बूत करना और ज़मीनी स्तर पर सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस की पारदर्शिता, जवाबदेही, क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पंचायतों के आंतरिक कार्य प्रवाह और मुख्य कार्य को स्वचालित करना और उनके कामकाज में ज़्यादा नागरिक-केंद्रितता लाना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस पहल के तहत प्रमुख (फ्लैगशिप) एप्लीकेशन में से एक ई-ग्राम-स्वराज है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा कामों की योजना, बजट, लेखांकन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के साथ ई-ग्राम स्वराज के एकीकरण से विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में मदद मिली है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।

साथ ही साथ, मंत्रालय द्वारा विकसित कई एप्लीकेशन पंचायतों के कार्यों को सुदृढ़ करते हैं और आम नागरिकों को जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं। मेरी पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर योजना, गतिविधियों और प्रगति से संबंधित डैशबोर्ड उपलब्ध कराती है। पंचायत निर्णय ग्राम सभा की कार्यवाही के संचालन और अभिलेखीकरण में सहायता करता है। ऑडिटऑनलाइन पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा देता है, जिसमें केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों का ऑडिट भी शामिल है।

(ख) मंत्रालय नई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर और परामर्शी और प्रतिक्रिया आधारित तरीका अपनाकर ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के प्रभावशीलता और असर को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। सुधार के क्षेत्र की पहचान करने और भविष्य के विकास को प्राथमिकता देने के लिए, क्षेत्रीय कार्यशाला और हितधारकों पर के साथ परामर्श के ज़रिए, अलग-अलग स्तर पर उपयोगकर्ताओं से नियमित प्रतिक्रिया इकट्ठा किया जाता है।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल और असर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों और पंचायत अधिकारियों से नियमित प्रतिक्रिया लिया जाता है और उसे शामिल किया जाता है। इन प्रयासों के तहत, मंत्रालय ने हितधारकों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए शिमला, हैदराबाद और गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया हैं। अपने ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन को मज़बूत करने हेतु रोडमैप बनाने और उस पर विचार-विमर्श करने के लिए, मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक उद्योग परामर्श कार्यक्रम, "मंथन" भी आयोजित किया। महाराष्ट्र और लखनऊ में भी हितधारकों के साथ खास बातचीत की गई। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाए रखने के लिए कई ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं।

सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस टूल्स समेत डिजिटल क्षमता निर्माण को मज़बूत करने के लिए खास पहल की है। मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के कामों के लिए धनराशि प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को क्षमता निर्माण करना है।

(ग) जी हाँ, मंत्रालय ने ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) के माध्यम से संशोधित आरजीएसए के तहत ई-गवर्नेंस पहलों का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन में योजना, लेखांकन और लेखा-परीक्षा की प्रक्रियाओं में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को अपनाने में हुई प्रगति को दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शिता, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पंचायती राज संस्थानों द्वारा सेवा प्रदायगी में सुधार हुआ है।

*****